राजस्थान मंडपम् व यूनिटी मॉल के खिलाफ दायर पी.आई.एल. सुप्रीम कोर्ट में खारिज

शीर्ष अदालत ने कहा कि, ''जयपुर की यह विवादित भूमि, वन भूमि नहीं है और आवेदन में कोई औचित्य नहीं पाया गया है''

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में राज्य सरकार की दो योजनाओं राजस्थान मंडपम व यूनिटी मॉल का निर्माण रोकने और इस जमीन को वन भूमि घोषित करने के लिए दायर पीआईएल को खारिज कर दिया। सीजेआई बी.आर.गवई व जस्टिस के. विनोद चन्द्रन ने यह आदेश टी.एन. गोदावर्मन मामले में दायर एक पीआईएल पर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित भूमि वन भूमि नहीं है और आवेदन में कोई औचित्य नहीं पाया गया है।

■ **ज्ञात रहे कि यूनिटी मॉल, जो प्रधानमंत्री की वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट पहल का हिस्सा है, तथा राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी टॉवर, फाइव स्टार और फोर स्टार होटल्स तथा रिहायशी टावर्स - ये सभी परियोजनाएं राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 95 एकड़ रीको भूमि पर अनुमोदित की गई है।**

याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि जयपुर की सांगानेर तहसील स्थित डोल का बाड़ क्षेत्र में इन परियोजना की जमीन वन भूमि है, और ऐसे में इसे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत संरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही यहां पर इन परियोजनाओं के निर्माण पर पाबंदी लगाई जाए।

जवाब में राज्य सरकार व रीको की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि संबंधित भूमि 1979 में औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई थी। इसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट तक तय किया जा चुका है। यह भूमि 1991, 2011 और 2025 के मास्टर प्लान में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अंकित है। इन परियोजनाओं को रोकने के लिए एक समूह के लोग बार-बार याचिकाएं दायर कर रहे हैं। ऐसी याचिकाएं पूर्व में भी एनजीटी व राजस्थान हाईकोर्ट में भी दायर हो चुकी हैं। इन याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर तथ्य छिपाने पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। राज्य सरकार ने परियोजना वाली जगह पर कोई पेड़ नहीं काटे हैं और केवल 56 पेड़ों को ही मंजूरी लेकर प्रत्यारोपित किया है। वहीं उनकी संख्या से 10 गुना अधिक पौधे वृक्षारोपण के तौर पर लगाए हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है। ज्ञात रहे कि यूनिटी मॉल, जो प्रधानमंत्री की वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट पहल का हिस्सा है, तथा राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी टॉवर, फाइव स्टार और फोर स्टार होटल्स तथा रिहायशी टावर्स - ये सभी परियोजनाएं राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 95 एकड़ रीको भूमि पर अनुमोदित की गई है।

'कागजों में नहीं धरातल पर काम चाहिए, स्कूलों की मरम्मत का निरीक्षण स्वतंत्र बॉडी से भी हो'

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की जर्जर स्कूलों को लेकर कहा है कि उन्हें कागजों में काम नहीं चाहिए, बल्कि काम धरातल पर दिखना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने स्कूलों में कराए जा रहे रिपेयरिंग के काम का निरीक्षण स्वतंत्र बॉडी से कराने की मंशा जताते हुए न्यायमित्र सहित सभी पक्षों को इसके लिए नाम सुझाने को कहा है। वहीं अदालत ने 31 अक्टूबर तक राज्य सरकार को प्रकरण में विस्तृत योजना पेश करने को कहा है। जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने से विद्यार्थियों की मौत के बाद प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने शपथ पत्र के जरिए जर्जर स्कूलों की मरम्मत को लेकर अदालत में जानकारी दी। महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि अधिक जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए पांच लाख रुपए का बजट तय किया गया है और आगामी मार्च माह तक काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं शेष स्कूलों में मरम्मत का काम नवंबर, 2026 तक पूरा कर लेंगे। अदालत ने कहा कि 5 लाख रुपए में मरम्मत कैसे होगी, लाखों रुपए तो रंग-सफेदी में ही लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि बिना परीक्षण किए सतही तौर पर यह राशि तय की गई है। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि जरूरत पडेगी तो और बजट जारी किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों के लिए कुल बजट का 11.46 फीसदी बजट स्वीकृत किया गया है। अदालत ने मरम्मत के काम के निरीक्षण का काम स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मंशा जताते हुए कहा कि ठेकेदार की गलती से घटनाएं होती हैं। ऐसे में पीडब्ल्यूडी से निरीक्षण कराने के बजाए स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाना चाहिए। अदालत ने महाधिवक्ता को कहा कि आप काम करने की बात कह रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज भी टीन शेड के नीचे स्कूल संचालित हो रही हैं। सभी जिलों की स्कूलों की ग्रेडिंग तय हो ताकि, काम को लेकर प्राथमिकता तय हो सके। इस पर अदालत ने कहा कि फिलहाल फोकस सुरक्षा को लेकर है। अदालत मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। वहीं स्वतंत्र संस्था से रिपेयरिंग का निरीक्षण स्वतंत्र एजेंसी से कराने के संबंध में सरकार से निर्देश लेने पडेंगे। एजी ने कहा कि नवंबर माह में केन्द्र सरकार से भी पैसा जारी होगा और उन्हें रोडमैप पेश करने के लिए समय दिया जाए। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को तय करते हुए सभी पक्षों को स्वतंत्र एजेंसी का नाम सुझाने को कहा है।

■ **राजस्थान में जर्जर स्कूलों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक राज्य सरकार को विस्तृत कार्य योजना पेश करने के आदेश दिए**

■ **अदालत ने यह आदेश झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने से विद्यार्थियों की मौत के बाद प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए**

सार-समाचार

डॉक्टर्स बैडमिंटन लीग के ट्रायल्स संपन्न

जयपुर। एसबीआई डीबीएल सीजन 7 के खिलाड़ियों के ट्रायल्स स्पॉफ़िट एकेडमी में संपन्न हुए। डीबीएल चेयरमैन डॉ. अनिल यादव ने बताया कि इसमें किड्स,बॉयज़ ,मेन्स व वुमेन्स केटेगरी में ट्रायल्स हुए। लीग संयोजक डॉ. हरीश भारद्वाज ने बताया कि मेन्स केटेगरी में डॉ. बन, डॉ. अक्षत, डॉ. शुभम, डॉ. रवि शर्मा, डॉ. श्रेय गुप्ता व डॉ. महेंद्र मीना ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया व चयनित हुए। आयोजन सचिव डॉ. हनुमान खोजा ने बताया कि वूमेंस केटेगरी में डॉ. दिव्या, डॉ. काशवी, डॉ. नेहा जांगिड, डॉ. नेहा शर्मा, डॉ. लावण्या व डॉ. रिशिता ने अच्छा प्रदर्शन कर प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान पक्का किया। लीग कोऑर्डिनेटर निधि पूनिया ने बताया कि बॉयज केटेगरी में देवांश, आदित्य, दर्शील, मोहित, विनय व महेंद्र ने प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाई। लीग कॉर्डिनेटर डॉ. दिलीप गुप्ता ने बताया कि किड्स केटेगरी में मित्रुका, रैना, दहीर, नयनिका, पूर्णव राशीष, अविन, क्षितिज, अदविल व प्रियांश ने प्रतियोगिता के लिए क्वालीफ़ाई किया। लीग कॉर्डिनेटर डॉ. सुधांशु शर्मा ने बताया की यह लीग 21 से 30 नवंबर तक

आयोजित होगी जिसमें जयपुर समेत लगभग 400 खिलाड़ी भाग लेंगे।

जेसीटीएसएल यूनियन ने सौंपा ज्ञापन

जयपुर। पुरानी पेंशन योजना के संबंध में 9 अक्टूबर को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश को वापिस लेने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम का ज्ञापन जेसीटीएसएल एम्पलाईज यूनियन एटक ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम विनीता सिंह को सौंपा। यूनियन के अध्यक्ष बोदूराम वर्मा ने बताया कि वित्त विभाग ने गत 9 अक्टूबर को आदेश निकाला था कि, आर्थिक रूप से कमजोर राज्य के बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, विश्वविद्यालय एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवानिवृत्त व मृतक कर्मचारियों के आश्रितों एवं सेवारत कर्मचारियों को जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम के तहत जमा राशि लौटने और पुरानी पेंशन योजना बन्द करने की छूट दी गई है। इस आदेश से कर्मचारियों में सामाजिक असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो रहा है, जिससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति गहरा आक्रोश है। पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिये बुढापे का सहारा और सामाजिक सुरक्षा का आधार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा जारी आदेश पुरानी पेंशन योजना से वंचित करने का अवांछनीय प्रयास है। इस आदेश में सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं को अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर पुरानी पेंशन योजना बन्द करने का आधार मिल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो लाखों कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा, जो कि उनके साथ अन्याय होगा।

30 से ज्यादा बसों के काटे चालान

जयपुर। जैसलमेर में बस में आग लगने के बाद राजस्थान परिवहन विभाग ने बसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान की शुरु डीटीओ आदर्श राघव के निर्देशन में की गई है। डीटीओ ने पांच टीमों के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाया है। टीम ने करीब डेढ से अधिक बसों की जांच है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जिन बसों परमिट ,फिटनेस और टैक्स जमा नहीं है। उन बसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। जिसके लिए पांच टीम बनाई गई है। पांचों ने करीब 150 से अधिक बसों की जांच की है। जांच के दौरान लगेज और क्षमता से अधिक सवारियां लेकर चलने वाली बसों के साथ ही बिना परमिट, फिटनेस और टैक्स के संचालित बसों पर कार्रवाई की है। अभियान के तहत राजस्थान परिवहन विभाग ने 30 बसों के चालान बनाए है। राजेंद्र शेखावत ने बताया कि यह विशेष अभियान दीपावली तक जारी रहेगा।

रीजीविका सदस्यों ने देखी प्रदर्शनी

जयपुर। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका), जयपुर के तहत लगभग 1000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने राजस्थान पुलिस द्वारा जयपुर एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में आयोजित नए आपराधिक कानूनों पर लाइव प्रदर्शनी में भाग लिया। यह प्रदर्शनी 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों तथा उनकी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रासंगिकता के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाना है। प्रदर्शनी को इस प्रकार तैयार किया गया है कि जटिल कानूनी प्रावधानों को इंटरैक्टिव डिस्प्ले, ऑडियो-विज़ुअल प्रस्तुतियों और लाइव डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से सरल और समझने योग्य बनाया जा सके। विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा, साइबर एवं डिजिटल अपराध तथा न्याय प्रणाली में सुधार से जुड़े प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया है।

एफएमडी नेटवर्क लेबारेट्री की समीक्षा बैठक

जयपुर। देश में पशुधन स्वास्थ्य सुरक्षा को सुद्ढ करने तथा खुरपका मुंहपका रोग (एफएमडी) नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए एफएमडी नेटवर्क लेबोरेट्री की 32वीं वार्षिक समीक्षा बैठक का दो दिवसीय आयोजन आज जयपुर में राज्य रोग निदान केंद्र, पशुपालन विभाग के तत्वावधान में संपन्न हुआ। संयुक्त निदेशक राज्य रोग निदान केंद्र डॉ. लोकेश कुमार शर्मा ने बताया कि।

प्रसारण निगम का नया पेंशन पोर्टल शुरू

जयपुर। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ने पेंशनधारी कर्मचारियों के लिए एक नया ऑनलाइन पेंशन पोर्टल शुरू किया है। अब पेंशन से जुड़ी जानकारी या दस्तावेजों के लिए कर्मचारियों को अब दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे, वे घर बैठे ही पेंशन सम्बन्धी सेवायें ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।प्रसारण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से पेंशनधारी कर्मचारी जीवित प्रमाण पत्र, पेंशन से जुड़ी रिपोर्ट, आदेश और भुगतान की जानकारी आसानी से ऑनलाइन देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

एस.एम.एस. अस्पताल में रिश्वतकांड के बाद तीन पुराने कर्मचारी हटाए

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। रिश्वत कांड में पकड़े गए सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के डॉ मनीष अग्रवाल के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने स्टोर शाखा में फेरबदल किया है।

■ **स्टोर कीपर को हटाकर स्टोर इंचार्ज का सौंपी जिम्मेदारी**

जिसमें प्रिंसिपल ने स्टोर शाखा के तीन कर्मचारियों को वहां से हटा कर उनकी जगह नए कर्मचारियों को नियुक्त किया है। इसके अलावा जो कर्मचारी सालों से स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत था, उसे हटाकर स्टोर इंचार्ज बना दिया गया है। कॉलेज के आदेशों के अनुसार, स्टोर शाखा (उपापन) में कार्यरत जगदीश प्रसाद यादव को हटाकर स्टोर कीपर बनाया गया है।

वहीं केदार प्रसाद स्वर्णकार (सामान्य शाखा) और ऋषि कुमार (संस्थापन शाखा) को स्टोर शाखा (उपापन) में नियुक्त किया गया है। सुरेन्द्र कुमार पाटीदार को स्टोर शाखा (उपापन) से सामान्य शाखा में, प्रमोद सिंह को लेखा शाखा से भंडार शाखा में और धनंजय सिंह को भंडार शाखा से लेखा शाखा में स्थानांतरित किया गया है।

इसके अलावा, शंकर लाल जलुथरिया, जो पिछले कई सालों से स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत थे, शंकर लाल जलुथरिया को अब स्टोर इंचार्ज बनाया गया है।

बताया जा रहा है कि रिश्वत कांड में पकडे गए डॉ मनीष अग्रवाल पर 11 शाखाओं का भार था , वो 11 शाखाओं का काम देखते थे। डॉ मनीष अग्रवाल के पास आईटी सेल, आरटीआई एवं लीगल सेल, महिला एवं जनाना हॉस्पिटल के सुपरविजन, पैरा क्लिनिक डिपार्टमेंट समेत कई अन्य विभागों का प्रभार था।बताया जा रहा है।

कि मेडिकल कॉलेज में स्टोर शाखा का महत्वपूर्ण रोल है। मेडिकल कॉलेज के अलावा इससे अटैच 7 अन्य अस्पताल में मेडिकल से जुड़े उपकरण तमाम सामान और दवाईयां सप्लाई होती है।

दिवाली से पूर्व 159 आवंटियों को मिले सपनों के घर के आवंटन पत्र

यू.डी.एच. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने लाभार्थियों को सौंपे दस्तावेज

जयपुर। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित समृद्धि अपार्टमेंट, जयपुर के 159 पात्र आवंटियों को बुधवार को उनके आवंटन पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने लाभार्थियों को उनके सपनों के घर के दस्तावेज़ सौंपे।

नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को हाऊसिंग बोर्ड की ओर से आयोजित शहरी सेवा शिविर में लाभार्थियों को आवंटन पत्र सौंपे। इस मौके पर आवासन अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि भी मौजूद थे।

यह आयोजन प्रताप नगर स्थित

■ **शहरी सेवा शिविर 2025 में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अब तक 2200 से ज्यादा प्रकरणों को निस्तारण किया**

मण्डल के वृत प्रथम कार्यालय में चल रहे शहरी सेवा शिविर 2025 अभियान के अंतर्गत किया गया। मंत्री खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि हर परिवार को सम्मानजनक जीवन देना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में हर सर को छत के संकल्प को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री खर्रा ने सभी 159 आवंटियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह घर केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत और आत्मनिर्भर जीवन की नींव हैं। उल्लेखनीय है की शहरी सेवा शिविर 2025 के माध्यम से हाऊसिंग बोर्ड ने अब तक लगभग 2200 से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण किया है।

आवासन अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अपनी योजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को प्राथमिकता दी है। समृद्धि अपार्टमेंट परियोजना आम नागरिकों को किफायती दरों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास प्रदान करने का सफल उदाहरण है। हाऊसिंग बोर्ड बोर्ड अब पारंपरिक निर्माण से आगे बढ़कर तकनीकी नवाचार व नागरिक सुविधा केंद्रित परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। आगामी समय में बोर्ड द्वारा राज्यभर में कई नई आवासीय परियोजनाएँ प्रारंभ की जाएंगी।

आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया की समृद्धि आवासीय योजना में प्रति फ्लैट की कीमत 35 लाख अनुमानित थी, लेकिन मण्डल ने उसी उच्च गुणवत्ता के साथ प्रत्येक फ्लैट 31 लाख में दिया है। मण्डल भविष्य में भी विभिन्न आय वर्ग के लिए इसी तरह किफायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले आवास उपलब्ध करवाता रहेगा।

एक अप्रैल से नवीन शैक्षिणक सत्र शुरू करने पर मंथन

जयपुर। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध कराने और पढ़ाई के दिवसों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग आगामी सत्र से एक बड़ा नवाचार करने की ओर अग्रसर है। इसके तहत विभाग अगला शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से आरंभ करने पर विचार कर रहा है। इस बाबत शिक्षा संकुल में शासन सचिव, स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभाग के पदाधिकारियों एवं शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से नए सत्र को एक अप्रैल से शुरू करने पर मंथन किया गया। बैठक में शासन सचिव कुणाल ने इस नवाचार के उद्देश्य बताते हुए कहा कि शैक्षिक सत्र में परिवर्तन से एनईपी 2020 के अनुरूप शिक्षण संभव होगा। इससे न केवल शिक्षण दिवसों की संख्या 180 से बढ़कर 210-220 दिवस तक हो जाएगी, बल्कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अधिक समय भी मिलेगा। इसके साथ ही सीबीएसई के शैक्षिणक कैलेंडर से एकरूपता स्थापित होने से विद्यालयों में नामांकन दर में वृद्धि की भी संभावना है।

इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की कथित समस्याओं को भी ध्यान पूर्वक सुना और उनके जल्द समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट ने उपस्थित प्रतिनिधियों से आवश्यक सुझाव आमंत्रित किए और विभाग की ओर से सभी आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया।

आयकर विभाग जयपुर रेंज प्रथम का एमटीएस गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय की जयपुर नगर तृतीय जयपुर टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग जयपुर रेंज-प्रथम एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) के विष्णु पारीक को दस हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर को परिवादी ने शिकायत दी कि उसकी फर्म साकेत जेम्स के आयकर रिटर्न वर्ष 2014-15 के आयकर अपीलीय

अधिकरण न्यायपीठ जयपुर द्वारा दिये गये फैसले में परिवादी के करीब 58 लाख रुपये आयकर विभाग को लौटाने का आदेश जून 2024 में दिये।

''विकसित राजस्थान 2047'' के विजन डॉक्यूमेंट पर काम कर रही भजनलाल सरकार

जयपुर (कासं)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ''विकसित भारत 2047'' के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी ''विकसित राजस्थान 2047'' विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसमें प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भजनलाल सरकार गरीब, युवा, महिला और किसानों के सशक्तीकरण को केन्द्र में रखते हुए इस विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक काम कर ही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बने इस विज़न डॉक्यूमेंट में राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में विकास के लिए लक्ष्य तय किये गए हैं। इनके अनुरूप प्रदेश में शत-प्रतिशत साक्षरता, कौशल आधारित शिक्षा, सुलभ एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, जलवायु अनुकूल-जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण और किफायती आवास सुनिश्चित किए जाएंगें। साथ ही, महिलाओं और युवाओं को कौशल, उद्यमिता एवं नेतृत्व के अवसर प्रदान कर उनकी राज्य के विकास यात्रा में भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

यह विजन चार प्रमुख थीम और 13 सेक्टर्स पर आधारित है। पहली थीम जनकल्याण और सामाजिक सशक्तीकरण है, जिसमें कृषि-खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेशन जैसे आयाम शामिल हैं। दूसरी थीम त्वरित विकास, समृद्धि और रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक, खनन और पर्यटन क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित की जा रही हैं। तीसरी थीम भविष्य उन्मुख राजस्थान की है, जिसमें आधारभूत अवसंरचना, जल सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थायित्व और जलवायु अनुकूलता को प्राथमिकता दी गई है। चौथी थीम संवर्धक नीति, वित्त और शासन की है, जो ग्रामीण व शहरी विकास, प्रभावी शासन, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने पर केंद्रित है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

■ **वर्ष 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य**

बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में वर्ष 2047 तक कृषि क्षेत्र में जलवायु अनुकूल और तकनीक आधारित खेती के माध्यम से उत्पादकता में 40 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में लाने, मातृ मृत्यु दर को 15 तक लाने, शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार जीवित जन्मों पर 10 से कम करने और जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। विजन डॉक्यूमेन्ट के अनुसार औद्योगिक विकास के माध्यम से राज्य में एक करोड से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 60 प्रतिशत से अधिक करने का संकल्प लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्यात को भी पांच गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा क्षेत्र को 33 गीगावाट से बढ़ाकर 290 गीगावाट करने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार यह विज़न डॉक्यूमेंट राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन द्वारा नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया है, जिसे राज्य मंत्रिमंडल ने 23 अगस्त को अनुमोदित किया था। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी13 अक्टूबर को विकसित राजस्थान-2047 की कार्ययोजना विमोचन किया।

इस दस्तावेज को राज्य, संभाग और जिला स्तर पर 1156 बैठकों के माध्यम से सुझाव प्राप्त कर तैयार किया गया है। विभिन्न स्तरों पर हितधारकों, विषय विशेषज्ञों, विभागीय अधिकारियों से गहन चर्चा तथा आमजन से प्राप्त सुझावों के आधार पर वर्ष 2030, 2035, 2040 और 2047 के लक्ष्य तय किए गए हैं। विजन के सफल क्रियान्वयन की दृष्टि से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। साथ ही, 45 विभागों को 13 सेक्टरों में विभाजित करते हुए नोडल विभाग नामित किए गए हैं तथा विभागीय स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाइयां भी स्थापित की गई हैं।

पंचायतीराज विभाग का अधिशाषी अभियंता रामवतार मीणा निकला करोडों का मालिक

ए.सी.बी. की टीमों ने ऑपरेशन ''भूदेव'' चलाकर रामवतार मीणा के जयपुर, करौली, गंगापुर सिटी और उदयपुर में एक दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) ने कार्रवाई करते हुए पंचायती राज विभाग इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के अधिशाषी अभियंता हाल एसोसियट प्रोफेसर रामावतार मीणा के विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज कर ऑपरेशन ''भूदेव'' चलाया। ए.सी.बी. ने रामवतार के जयपुर, करौली, गंगापुर सिटी व उदयपुर में स्थित एक दर्जन ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया। एसीबी को सर्च कार्यवाही में करोड़ों रूपये के आलीशान मकान और फार्म हाउस होने की पुष्टि हुई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय को गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी कि पंचायती राज विभाग,इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के अधिशाषी अभियंता हाल एसोसियट प्रोफेसर रामावतार मीणा द्वारा पद पर रहते हुए रिश्वत प्राप्त की जाकर भ्रष्ट तरीके से भ्रष्टाचार के द्वारा स्वयं एवं अपने परिवारजनों के नाम से अपनी वैद्य आय से अनुपातिक रूप से अधिक चल-अचल सम्पतियां

आरोपी रामवतार मीणा

अर्जित की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करोड़ों रुपए है।

इस शिकायत का एसीबी की इंटेलिजेंस टीम ने गोपनीय रूप से सत्यापन किया गया तथा अधिकारी द्वारा जयपुर, गंगापुर सिटी, करौली, उदयपुर के विभिन्न स्थानों पर आवासीय भूखण्ड, प्लांट्स, फार्म हाउस, कन्स्ट्रकशन कम्पनी, अर्जित करने के तथ्य प्रकट हुए। जिस पर विस्तृत रूप से तथ्य संकलित किये गये एवं तथ्यों की जाँच होने पर करीब 2.77 करोड़ (करीब 115 प्रतिशत) की परिसम्पत्तियां वैद्य आय से अधिक अर्जित का मामला बनना पाया जाने पर

■ **करोड़ों रूपये के आलीशान मकान और फार्म हाउस होने की पुष्टि हुई**

प्रकरण दर्ज किया गया।

जिस पर ए.सी.बी. जयपुर नगर प्रथम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र अनुसंधान अधिकारी के नेतृत्व में सक्षम न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त कर एसीबी की एक दर्जन से अधिक टीमों ने एक साथ बुधवार अल सुबह अधिशाषी अभियंता हाल एसोसियट प्रोफेसर रामावतार मीणा के जयपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर एवं उदयपुर के विभिन्न स्थानों पर आवासीय भूखण्ड, प्लाट्स, फार्म हाउस, केसर, कन्स्ट्रक्शन कम्पनी करीब एक दर्जन विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की कार्यवाही की गयी।

अब तक कि गयी सर्च कार्यवाही प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित जयपुर शहर में इन्दिरा गांधी नगर में प्राइम लोकेशन पर 6 बडे प्लाट/मकान, जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में रोहिणी नगर टीलावाला में करोड़ों रूपये की बेनामी सम्पति, जयपुर के अचलपुरा कोटखावदा में मुख्य मार्ग पर बेशकीमती व्यावसायिक उपयोग के लिए लाखो रूपये की कृषि भूमि में निवेश, खिरखिड़ा गांव करौली में करीब 5 बीघा का खेत/फार्म हाउस, जिसमे लाखों रुपये का निर्माण कार्य हो रखा है। गंगापुर सिटी में दो मंजिला मकान एवं गंगापुर सिटी के जमीन चल-अचल संपत्ति होने की पुष्टि हुयी।

आरोपी द्वारा इन्दिरा गांधी नगर जयपुर में करीब 7500 वर्गफीट में एक आलीशान कोठी का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें अब तक करीब एक करोड़ रुपये का व्यय करना प्रकट हुआ है। जयपुर स्थित आलीशान मकान व खिरखिड़ा करौली स्थित फार्म हाउस, गंगापुर सिटी स्थित आलीशान दो मंजिला मकान आदि में करोडो रुपये व्यय होने का अनुमान है। मकान, फार्म हाउस की कीमत का आकलन तकनीकी विशेषज्ञ अप्रूव्ड वैल्यू के अनुसार करवाया जा रहा है। तलाशी के दौरान करीब 3 लाख रुपये एवं लाखो रूपये का महंगी लग्जरी वाहन, जीप कम्पास होने की पुष्टि हुयी। सर्च कार्यवाही में आरोपी द्वारा अपनी पत्नी के नाम से कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एवं माइनिंग लीज होने की पुष्टि हुई। जिसमें आरोपी द्वारा करोड़ों रुपये का निवेश करना सामने आया।